

2021 20 GGI 2019

2021-22

4. 2021-22 (Dec. 30, 2021)

- 07.03.2021 (MDONER) ...
• 08.03.2021 (2021-22) ...
• 09.03.2021 ...
• 10.03.2021 ...

5. 2021-22 (Dec. 23, 2021)

- 1 - 75.87 ...
2 - 75.73 ...
4 - 75.67 ...
5 - 74.87 ...
• 11.03.2021 (2030) ...
• 12.03.2021 (NEC) ...
• 13.03.2021 (MDoNER) ...
• 14.03.2021 ...
• 15.03.2021 ...

- 2019-2020 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में, 'एनएसडी' (National Skill Development Corporation) के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

2. 'एनएसडी' (National Skill Development Corporation) के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

- एनएसडी के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह बजट आवंटन 2021-22 के लिए है।
- एनएसडी के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह बजट आवंटन 2021-22 के लिए है।
- एनएसडी के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह बजट आवंटन 2021-22 के लिए है।
- एनएसडी के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह बजट आवंटन 2021-22 के लिए है।

3. 7 अक्टूबर 2021 को IISF का आयोजन किया जाएगा।

- 7 अक्टूबर 2021 को IISF का आयोजन किया जाएगा।
- 7 अक्टूबर 2021 को IISF का आयोजन किया जाएगा।
- IISF 2021 का आयोजन किया जाएगा।

4. 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में, 'एनएसडी' के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

- 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में, 'एनएसडी' के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में, 'एनएसडी' के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में, 'एनएसडी' के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

5. एनएसडी के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

- एनएसडी के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- एनएसडी के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- एनएसडी के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

- 2019-2020 (2019-20), 2020-21 (2020-21) की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।
- 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।

“संविधानसभा के उद्देश्यों का विवरण”

- 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।
- 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।
- 1971 की वृद्धि दर 2019-20 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 1971 की वृद्धि दर 10.8% थी, जो 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% से कम है।

14. 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।

- 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।
- 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।
- 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।

15. 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।

- 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।
- 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।

2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है। 2019-20 की वृद्धि दर 7.4% थी, जो 2018-19 की वृद्धि दर 7.83% से कम है।

- (A) 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है।
- (B) 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है।
- (C) 2019-20 की वृद्धि दर 2018-19 की वृद्धि दर से 0.43% कम है।

- 49. **प्रवासी कल्याण (FCPL)** का निदेश जारी कर केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (RHT) के अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया है।
- 50. **प्रवासी कल्याण (FCPL)** का निदेश जारी कर केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (RHT) के अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया है।
- 51. **प्रवासी कल्याण (FCPL)** का निदेश जारी कर केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (RHT) के अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया है।
- 52. **प्रवासी कल्याण (FCPL)** का निदेश जारी कर केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (RHT) के अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया है।

19. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।**
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।**
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।**

20. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।**
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।**
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।**

7. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।**
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।**
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।**

8. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।

8. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।

Relevance: Recently violence has erupted in Nagaland after Indian Armed Forces have 'mistakenly' killed the civilians. The killing of civilians in Mon district has cast a shadow on the already struggling peace talks between the Centre and NSCN (I-M). This has also led to further protests related to removal of the Armed Force Special Protection Act (AFSPA).

Background and History:

- Maoist guerrilla leaders Isak Chisi Swu, Thuingaleng Muivah and S S Khaplang had created the NSCN in 1980 to oppose the decision of the Naga National Council (NNC) to accept the Indian Constitution-the 1975 Shillong Accord was signed by Angami Zapu Phizo-led NNC.
 - On August 14, 1947, the Naga National Council (NNC) led by Angami Zapu Phizo declared independence for Nagaland. Phizo formed an underground Naga Federal Government (NFG) and a Naga Federal Army (NFA) in 1952, in response to which the Centre sent in the Army and enacted the Armed Forces (Special) Powers Act, or AFSPA.
- After differences between the top leaders, the group split into the NSCN-IM and the NSCN-K.
- In 1997, the NSCN-IM agreed to a ceasefire which led to the start of almost two decades of peace talks with the Indian government.
 - It refers to **ongoing talks between the Indian government and Naga insurgent groups**, in particular the NSCN(IM), since 1997 with the aim to sign a Naga Peace Accord.
- The 2015 agreement was signed between the Centre and the Naga groups led by National Socialist Council of Nagaland-Isak-Muivah (NSCN-IM) after the latter agreed to give up its long-standing demand for sovereignty.
 - There was a broad understanding of a settlement within the Indian constitutional framework, with due regard to the uniqueness of Naga history and tradition.
- The process, however, halted when the group insisted on a **separate flag as well as the inclusion of all Naga-inhabited areas in one administrative apparatus**.
 - The NSCN-IM's "**Greater Nagalim**" consists of present Nagaland and all contiguous Naga-inhabited areas, which includes many districts of Assam, Arunachal Pradesh and Manipur, and most interestingly, a part of neighbouring Myanmar.

Major Issues and Concerns

- Most of the states except Plains of Assam were deliberately excluded from mainstream government administration of Britishers and categorised as excluded areas in Government of India Act 1935 and the ethnic people were called backward tribes. This has led to the exclusion of the ethnic people from the rest of India.
- Recent killings of civilians have invoked the demand of removal of AFSPA which gives armed forces special powers to control "disturbed areas", which are designated by the government.
 - Under its provisions, the armed forces have been empowered to open fire, enter and search without warrant, and arrest any person who has committed a cognisable offence, all while having immunity from being prosecuted.
 - Currently, AFSPA is in effect in **Jammu and Kashmir, Nagaland, Assam, Manipur (excluding seven assembly constituencies of Imphal) and parts of Arunachal Pradesh**.
- Naga people consider the act as "decurian" and have been asking for its removal for a long time.

- Further, these killings could be exploited by certain insurgent groups to recruit and even strengthen the hands of the NSCN(I-M), which will likely push for its demands and adding fuel to the insurgency in the North east areas.
- The current demands of the NSCN (IM) have toned down from complete sovereignty to a **greater autonomous region** within the Indian constitutional framework.
- They have been asking for a **separate Naga flag** also.
- The unrest in the region is a great challenge to the internal security of border areas as it continues to get young recruits and wields considerable influence in the region.
- After the removal of the interlocutor N. Ravi by the centre, the state has been waiting for the new appointment.

Government's Stand

- According to the Gol, AFSPA is a "a very simple measure" to control the "misguided Nagas indulging in mischievous activities".
- Further, over such a vast area to depute civil magistrates to accompany the armed forces is not possible.
- There is no way the government would accept a separate constitution for Nagaland as it is against the sovereignty of India.
- The idea of providing a separate flag was also weakened after Kashmir region's flag was taken away in 2019.
- Gol considers Nagaland as an inseparable part of the country and is taking security measures to strengthen the border areas by curbing the insurgent groups.
- Gol considers that accepting the demand of a particular group will give rise to the separatist tendency in the entire northeast which would be against India's overall security and sovereignty.

Conclusion:

- The Naga insurgency, rooted in Naga nationalism, is one of the oldest insurgencies in the country. Lasting peace in the Northeast is not possible without resolving the Naga insurgency.
- It is important to understand that there cannot be an accord without the NSCN(IM). The idea is to slowly bring them to accept what India can give without compromising the country's sovereignty and security.
- For the same there is a need to have collaborative talks between the centre and state and the separatist group as well. Gol must consider the suggestions given by the Jeevan Reddy Committee formed in 2004 which had recommended a complete repeal of the AFSPA.
- Setting up **Bicameral Assembly with at least 40 nominated members** representing different tribes; **absorption of cadres as local armed forces or in the Indian paramilitary**; setting up of **autonomous councils in Naga-dominated areas** of neighbouring states; and the **use of the Naga flag for at least customary events** can provide amicable solutions to the current crisis.

Sources:

<https://indianexpress.com/article/explained/naga-peace-talks-nagaland-insurgent-group-7533021/>

<https://economictimes.indiatimes.com/news/india/two-issues-are-holding-up-the-naga-solution-under-the-ongoing-indo-naga-political-talk-nscn-im/articleshow/87042545.cms?from=mdr>

<https://indianexpress.com/article/opinion/columns/nagaland-insurgency-peace-accord-pm-modi-5545506/>

<https://www.thehindu.com/news/national/other-states/naga-issue-signing-of-new-pact-to-bring-new-developments-says-neiphiu-rio/article37399806.ece>

10. 1948301332222222 17223933322222 (304813232222) 03273928392222 (2942 09 2A48 09) 224902 082747 3847 03273913 22022639224802 1348 09224830 30 33304837 3847 1322 3948 (Dec. 15, 2021)

1547022648304022 174339 220224483048 38483848 05223922 363939 2847 324813382839 1348 38421A3922 15392939 1339:

- 2018, 2019 0438 2020 224702 174839193928422848 17243939392739 (304813232222) 03273928392222 (2942 09 2A48 09) 1967 1347 243924 1739392848243939 153909 1709 32172817 53% 35482913482439 30 33304837 3847 1322 062941 1347 254764
- 0839384829292222 1348 2709222928 224702 39182447 394909 39244824 224702 2949092A4809 224702 380238482728 15392939 172939 2939, 1438 3830133939 224809393939 "39394824222928 224702 2942092A4809 224702 134808 380238482728 35391A393929294828 28394802 3948" 6484
- 2020 224702, 30 33304839 3847 1322 062941 1347 354829134824392929292929 1348 2942092A4809 1347 243924 38293847 03273913 173939284824393948 0924482439 2A4838284738 (205) 224702 394108, 09381347 223928 2229482942 1439 133848294839 (166), 2223392A4139 (113), 1438 133938180221 (35) 224702 39410864